eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

उदारीकरण, वैश्वीकरण की चुनौतियां

1डा0 सरनपाल सिंह

1सह प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय तिलहर, शाहजहांपुर, उ0प्र0

Received: 15 June 2018, Accepted: 15 July 2018, Published on line: 15 Sep 2018

Abstract

एक तरफ 50 के दशक में विश्व के सभी राष्ट्रों में विकास के प्रति सर्वव्यापी जागरूकता आयी तथा विकासशील देशों ने सोवियत रूस अथवा अमेरिका के माडल पर चलकर विकास करनें का प्रयास किया। यह बात अलग है कि अपने ऐतिहासिक बाहयताओं के कारण विषम आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण तथा मानवीय संसाधनों तथा तकनीक के विकास में अक्षमता के कारण विकासशील देशों की विकसित देशों में असमानता बढ़ती चली गयी। इन देशों में सम्पन्नता बडी है, सांधनों का उपयोग बढ़ा है उत्पादन तथा अतिरेक बढ़ा है, उधोगो का तकनीकी ढांचा भी बदला है, परन्तु उन्होनें मुख्यतः विकसित देशों के प्रतिमानों की नकल की है इसलिए उनका विकास विकसित देशों की तुलना में कम रहा है तथा तकनीकी विकास भी द्वितीय श्रेणी का रहा है बावजूद इसके लिए विकासशील देशों को भारी कीमतें चुकानी पडी है।

परिचय

विकासशील विकसित देशों पर विकास के लिए निर्भर है, अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार की शर्ते उनके प्रतिकूल रही है व अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार अवसर उनके शोषण का माध्यम बना है (देखे गुन्नार मिडिल : एशियन ड्रामा)। इसलिए इन देशों में संरक्षण के प्रति झुकाव सदैव बना हुआ है। परन्तु विकास की संस्थानात्मक बाधाओं, अवस्थापना सम्बन्धी कमियों, बेलोच ढांचें तथा तेजी से बढ़ती जनसंख्या दबाव या उपभोग तथा साधनों के उचित प्रबंधन न होने के कारण उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नही हुई। संरक्षण से इन्हे वाछिंत लाभ मिला या नही, यह एक अलग खोज का विषय है, परन्तु 80 के दशक तक आते आते विकासशील देशों में बन्द अर्थव्यवस्था की वाहनीयता पर बहस अवश्य शुरू हो गयी। अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार संगठन तथा मौद्रिक संस्थाओं ने भी अल्पविकसित देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे यदि अर्थव्यवस्थाओं को विश्व व्यापार के लिए खोले। तथा विश्व स्तर का आर्थिक ढांचा तैयार करे ताकि आर्थिक शक्तियां इन देशों में स्वंतत्र व कुशल तरीके से कार्य कर

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

सके। विदेशी विनिमय का संकट झेल रही अर्थव्यवस्थाओं के पास और कोई चारा भी नही था वे विदेशी मोंचे तथा आन्तरिक मोंचे दोनो पर पराजय का सामना कर रही थी अतः 1993 में विश्व के बहुसंख्यक देशों ने गैट (Geueral Agreement on Trade & Tarrift) पर हस्ताक्षर कर दिये।

अब उदारीकरण की विश्व अवधारणा पर चर्चा करे यह मुख्यतः तीन चीजों उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की धारणाओं का संयुक्त संकल्प हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के व्यापार व उधोग पर लगें आन्तरिक व वाह्य आयात पर प्रतिबधों की समाप्ति अपनी आर्थिक संस्थाओं को विश्व स्तर का बनाना तथा निजी पूंजी का सभी क्षेत्रों में कार्य करने की छूट देना है। उदारीकरण का दर्शन सार्वजनिक उपक्रमों को नकारता नही है परन्तु साधनों के efficient use अर्थात प्रभावी उपयोग पर जोर अवश्य देता है।

उदारीकरण दर्शन के रूप में निम्न आधार स्तम्भों पर स्थापित है।

1, निजी क्षेत्र साधनों के प्रंबधन में अधिक कुशल होता है।

2. बाजार में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थापना होगी। जिसमें केवल कुशल इकाइंया ही जीवित रहेगी तथा अकुशलता स्वंय ही समाप्त हो जायेगी। पूर्ण प्रतियोगिता की शक्ति संसाधनों के आवंटन तथा वितरण में कुशलता स्थापित होगी। उत्पादन अधिकतम होगा तथा ग्राहकों को भी न्यून्तम लागतों पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। इसके ग्राहकों का अतिरेक भी अधिकतम हो जायेगा।

3. सरकार तथा उसके उपक्रम साधनों के वितरण, आवंटन, उत्पादन आदि में कुशल नही होते। निजी लाभ की प्रेरणा को लम्बा बनाते है। नीचे के स्तर कर्मचारी निर्णय के ऊपर के कर्मचारी का मुंह देखता है और ऊपर वाला और ऊपर वाले का। इन उपक्रमों में सार्वजनिक हितों के नाम पर कर्मचारीगणों तथा संचालको के द्वारा अपना हित साधा जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी उच्च स्तर की नौकरी की सुरक्षा की भावना से ग्रस्त होता है और उनमें दायित्व बोध की बजाये अधिकार बोध अधिक होता है। इन उपक्रमों के बाजार से प्रतियोगिता का सामना नही करना पड़ता है यदि निजी क्षेत्र अंकुश में रहे तो। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में इनमें प्रशसित मूल्यों की आड़ में अपनी कुशलता व घाटों को छिपाने की मुत्सित प्रवृत्ति पायी जाती है। और इनकी एकाधिकार शक्ति भी समाज को निरंतर कष्ट देती है क्योंकि यदि घाटें लगातर हो रहे हो तथा एक Secular

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

Trend के रूप में जारी हो तो इन घाटों को विदेशी सहायता, आन्तरिक ऋण अथवा करों के माध्यम से पोषित किया जाता है जो पूरी अर्थव्यवस्था में संकट का कारण बनता है। सरकारी उपक्रमों में अकुशलता तथा स्टाफ की ऊंची तनख्वाहों के चलते लागते बढ़ती जाती है जबकि उत्पादकता या उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण का कोई उपाय इन उपक्रमों में नहीं किया जाता है। बाजार में अत्यंत अल्प दामों में अच्छी गुणवत्ता की चीजें मिलती है, उनकी बजाय अत्यधिक निम्न गुणवत्ता की वस्तु बाजार कीमतों से कई गुना ऊँचें दामों पर खरीदी जाती है और इस खरीद में सरकारी उपक्रमों के अफसर, सप्लाई ठेकेदार, राजनीतिक व्यक्ति कमीशन के रूप में काला धन प्राप्त करते हैं। सरकारी सड़कों की निमार्ण कार्यो की गुणवत्ता उन पर व्यय किये गये धन की तुलना में अत्यधिक निम्न श्रेणी का होता है। इस प्रकार 'हरि अनंत हरि कथा अनन्ता' की तर अनन्त तरीके से कर, सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त धन तथा विदेशों से अत्यंत ऊंची लागत पर अर्जित ऋणों के संसाधनों का क्षरण सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार होता है। राष्ट्रहित के नाम पर, गरीबों के नाम पर चलायी जा रही योजनाओं की वास्तविक स्थिति भी किसी से छिपा नही है।

अतः उदारीकरण के दर्शन के एक अंग के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रंबध को अधुनातन करने उसमें निजी प्रबंध को महत्वपर्ण भूमिका सौपनें, सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा इक्विटी मार्केट से संसाधन जुयने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने, सरकारी उपक्रमों में विनिवेश, सरकारी उपक्रमों का स्वायत्त तथा जिम्मेदार (accountable) बनाने, रूग्ण सार्वजनिक उधोगों को समाप्त करने तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करने के अवसर देने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार अपनी आर्थिक संस्थाओं को मजबूत बनाने का एक तरीका है। केवल उन्ही क्षेत्रों में ही सरकारी उपक्रमों का कार्य करना चाहिए जहां उनकी अत्यंत जरूरत है, निजी क्षेत्र समर्थ नही है, तथा जहां पर सरकारी निवेश पर 8 प्रतिफल ब्याज की दर से अधिक अवश्य हो। अतः यह कहा गया है कि निवेश (सरकारी) को केवल सामाजिक व आर्थिक अधोसंरचना कायम करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित होना चाहिए और वर्तमान स्थिति तो यहां तक पहुंच चुकी कि शिक्षा के जलापूर्ति का, चिकित्सा, बिजली आदि के भी निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और वर्तमान अवधारणा अब यह हो गयी है कि सरकार को समाज कल्याण योजनाओं पर, ग्राम व गरीब के उत्थान पर, कृषि व उधोग के विकास पर दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च करने वाली राशि को समाप्त करके केवल एक विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क स्थापित करने पर जोर देना चाहिए।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

सरकार का आकार तथा सरकारी मशीनरी के आकार को घटाने के लिए श्रम कानूनों में भी संसोधन करना चाहिए और सार्वजनिक अपव्यय को भी जहां तक हो सके कम करना चाहियें।

4. विगत पांच वर्षो में संरक्षण का भारतीय उघोगो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सामान्य भारतीय ग्राहकों का शोषण हुआ है। तथा संरक्षण का प्रयोग उन्होनें अपने उत्पाद का विकास करने, तकनीक का विकास करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण की प्रविधिया को विकसित करने की अपेक्षा उन्होने अपने उत्पाद की गुणवत्ता कम करने ऊंची कीमतें निर्धारित करनें, कालाबाजारी व जमाखोरी करने, अनुचित मुनाफा करनें, ग्राहकों का नाजायज शोषण करनें, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने आदि कार्यो के लिये ही किया गया है। इससे वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी नही रह पाये और भारत को निर्यात के मोर्चे पर लगातार नीचा देखना पडा है और देश लगातार भुगतान संतुलन का संकट झेल रहा है। निर्यात को इतनी आर्थिक छूटें दी जाती है इतनी कर रियायतें व सब्सिडी दी गयी है परन्तु हमारा भुगतान, संतुलन सदैव प्रतिकूल रहा है। कई मामलों में तो निर्यात केवल निर्यात सब्सिडी व कर छूट का लाभ उठानें के लिए ही किया जाता है। निर्यात करों से आयाता करों की तुलना में मात्र नाम मात्र में (2–3 प्रतिशत) राशि प्राप्त होती है। भारतीय उद्योगों की प्रगति विश्व परिदृश्य की तुलना में संतोषजनक नही रही है।

5. स्वंतत्र व्यापार में कुशल उद्योगों को अपने आप को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी स्वंतत्र व्यापार से अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के लाभ (Gasins from trade) मिलेंगे, अर्न्तराष्ट्रीय कुल व्यापार तथा उत्पादन में वृद्धि होगी, विशिष्टीकरण बढ़ेगा तथा मार्केट के आकार की समस्या भी कम होगी व मार्केट का आकार बढ़ेगा। अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार से लाभों का बंटवारा व्यापार शर्तो (Terues of Trade) के अनुसार होगा। अकुशल फर्मे समय के साथ धीरे धीरे सामप्त हो जायेंगी। कुल मिलाकर संसाधनों के अकुशल प्रयोग की समस्या हल हो जायेगी तथा देश विशिष्टीकरण की ओर बढ़ेगे और उसमें तकनीक का हस्तांतरण महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। विशिष्टीकरण के फलस्वरूप बड़े पैमानें के उत्पादन में वृद्धि तथा बेरोजगारी में कमी आयेगी (या देश में जो साधन कम लागत पर उपलब्ध है, उसका अधिक प्रयोग होगा) असमानता में कमी आयेगी तथा अल्प विकसित देशों की गरीबी भी दूर हो सकेगी।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

6. उदारीकरण के फलस्वरूप विश्वस्तर की आर्थिक संस्थायें विकासशील देशों में विकसित होंगी। बहुत बडें पैमानें पर विदेशी पूंजी तकनीक व दक्षता की आवश्यकता के साथ ही साथ वैश्विक कार्य संस्कृति का भी आगमन होगा जो कि व्यक्ति क मानसिक लक्षणों तथा व्यक्तित्व को बदल डालेगी। भारतीय व्यक्तित्व भी इमानदारी से काम करनें वाला, दक्ष, विकसित, उच्च उत्पादक (Highly Production) कुशल तथा ऊंची तनख्वाहें प्राप्त करनें वाला बन जायेगा तथा भारतीय लोगों के जीवन स्तर में आमूल चूल परिवर्तन आयेगा। भारतीय उघमियों को भी व्यापार हेतु अर्न्तराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो जायेगा। निर्यात में वृद्धि हो जायेगी तथा आयातों की गुणवत्ता बढ़ेगी। भुगतान संतुलन में स्थायी सुधार आने की भी संभावना है यदि भारतीय फर्मे गुणवत्ता युक्त उत्पाद जिसकी मांग विदेशी बाजारों में अधिक हो उत्पादन तथा निर्यात बढ़ानें में सफल हो सकें।

7. सरकार को आयात आधारित उघोग लगाने, परियोजनाएं चलाने इसके लिए अर्न्तराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं के आगे ऋण हेतु हाथ पसारनें की कोई आवश्यकता भविष्य में नही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा यह काम हो सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मुख्यतः कोर क्षेत्रों में प्रभावी रूप से आमंत्रित करनें की समस्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ–साथ विदेशी तकनीक का अन्तरण भी प्रभावी रूप से होगा जिसके लाभ उत्पादकता वृद्धि आय वृद्धि के रूप में दिखायी देगें। विदेशी तकनीक के अन्तरण के संबंध में एक सर्वाधिक मजबूत तर्क यह दिया जाता है कि भारत में अभी तक विदेशी तकनीक आयात केवल आयोजित रहा है, विदेशी फर्मो के साथ स्वदेशी फर्मो को सीधे सीधे तकनीक सहयोग की इजाजत नही रही है और न ही विदेशी तकनीक सभी क्षेत्रों मे आयी है, फिर भी भारतीय उघोगों का तकनीकी ढाँचा आधारभूत रूप से बदला है, भारत विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात तथा कच्चे माल व अति आवश्क पेट्रोलियम, मशीनरी तथा कैपिटल गुड्स का आयात ही कर रहा है। इस प्रकार तकनीक क आयात, अन्तरण व Absorption (अर्न्तग्रहण वचायन) ने भारतीय निजी क्षेत्रों को (प्रतिबंधित तथा सीमित होते हुए भी) तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को तथा व्यापक रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है और फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का ढाँचा ही परिवर्तित हो गया है। आज हम विश्व की प्रथम दस औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यदि तकनीक का अन्तरण तथा निजी क्षेत्र दोनो स्वतंत्र हो जायेगी तो निश्चित ही तकनीक के वृहद स्तर पर आयोग के लाभ प्राप्त होगें। उदाहरणार्थ दूर संचार तथा सूचना उद्योग में भी अच्छी वृद्धि हुई है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

8. उदारीकरण के पीछे एक अर्न्तनिहित मान्यता यह भी है कि सरकार उन चीजों को जिन्हें समाज के गरीब व पिछडे वर्ग नही खरीद सकते है कुछ प्रावधान कर सकती है परन्तु इसकी कीमत निजी क्षेत्रों को बाधित करके नही वसलूनी चाहिए। बाजार प्रक्रिया में अपने खतरे है उतार चढ़ाव है, हानि लाभ है, व्यापार की असुरक्षा है, शोषण की संभावनाऐं है। सरकार इन्हे ध्यान में रखकर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा का नेटवर्क तैयार करेगी परन्तु इनमें संसाधनों को इस प्रकार व्यय करेगी कि व्यय धन की सीमान्त प्रतिफल (जो सामाजिक सुरक्षा पर व्यय होगा) प्रभावित व्यक्तियों को (जो सामाजिक सुरक्षा के वास्तविक हकदार है) कम से कम इतना अवश्य मिलेगा जो मार्केट में उस धन के निवेश पर प्राप्त होगा। इसके साथ–साथ ही यह धन निजी क्षेत्रों में निवेश तथा उत्पादन पर न लगाकर उसी व्यक्ति समूह की समग्र आय के उस भाग पर कर लगाकर प्राप्त किया जाये उसे उपभोग किया जा रहा है अर्थात उपभोग करने वाली इकांइया अर्थात वही व्यक्ति समूह।

9. उदारीकरण के समर्थक यह मानते है कि मनुष्य अपना ख्याल रखने के लिये या अपने हितो की रक्षा के लिय पर्याप्त शक्तिशाली है एडम स्मिथ का 'अदृश्य हाथ' सभी कमियों को दूर करने में सक्षम है तथा यदि इस हाथ को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दिया जाये तो यह नयी आर्थिक संस्थाओं का प्रौद्योगिकी का तथा मनुष्य की आर्थिक शक्तियों के अनुसार अपने को ढालनें की शक्ति का विकास अपने आप कर सकता है तथा विकास का एक अच्छा उपकरण साबित हो सकता है। बाजार क्रूर है तथा कमजोर व्यक्तियों को संकट में डाल सकता है परन्तु संकटो से गुजरकर ही मानव सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

10. उदारीकरण के लाभ इस परिकल्पना पर आधारित है कि निजी पूंजी दोष मुक्त होती है तथा मानव के कल्याण या अकल्याण के प्रति तटस्थ है इसे सिर्फ मुनाफे से मतलब है। बाजार का आकार जैसे जैसे बढ़ता है अपूर्ण प्रतियोगिता से पूर्ण प्रतियोगिता की ओर गति होती है। बाधाऐं केवल अनुचित सरकारी हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती है और बाजार शक्तियों के काम में अनुचित दखलेदाजी चाहे वह प्रत्यक्ष नियमों व कानून की शक्ति के अनुसार हो या सरकारी उपक्रमों को व्यवसाय में उतारकर बाजार को प्रभावित करने की जुगत दोनो गलत है। श्रीमती भार्गरेट थैचर के शब्दों में "Government has no business to be in business". सरकार का काम केवल बाजार यंत्र को मात्र आर्थिक शक्तियों के अनुसार काम करने को निर्देशित करना है तथा वास्तविक बाजार शक्तियों के संतुलन को निर्धारित करने वाले तत्वों मे अनुचित गतिविधियों के प्रभाव पर अंकुश रखना है। अगर बाजार में

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

पूर्ण प्रतियोगिता हो (साधनों तथा उत्पाद दोनो बाजारों मे) तो उपभोक्ताओं तथा उत्पादक साधनों दोनों के शोषण का रास्ता काफी हद तक बंद हो जाता है। साधनों को उनकी सीमान्त उत्पादकता के आधार पर भुगतान मिलता है तथा थुलर प्रमेय के अनुसार समस्त उत्पाद इस विधि में वितरित हो जाता है तथ अनुचित वितरण का खतरा भी कम हो जाता है। जितना अधिक बाजार पूर्ण प्रतियोगिता के नजदीक होगे, लोगो का कल्याण, सैम्युलसन–बर्गर सिद्धान्त के अनुसार, उतना ही अधिक होगा।

इस प्रकार उदारीकरण के दर्शन में मनुष्य की उपयोगिता उसके मनुष्य मात्र होने पर आधारित न होकर बाजार के एक उपभोक्ता के रूप में उसकी पाकेट के आकार तथा उत्पादक साधन के रूप में उसकी उत्पादकता पर आधारित है। उसमें इस बात का कोई आधार नही है कि बाजार की खोज तथा व्यापार के नाम पर अतीत में किस प्रकार उपनिवेशों का भयंकर शोषण किया गया तथा भविष्य में ऐसा नही किया जा सकेगा। ऐसा भी निश्चित नही है कि अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार खुलने मात्र से अल्पविकसित देशों की कुछ विकास शर्तो में कुछ सुधार अवश्य ही होगा, या पर्याप्त सुधार होगा। तकनीक का स्थानांतरण भी अभी तक इन देशों में पर्याप्त नही रहा है, खासकर उन देशों मे जहां संरक्षण का सहारा शुरू से नही लिया गया है और तकनीक के प्रभावी अन्तरण या तकनीकी विकास के लिए अल्पविकसित देशों को विकसित देशों को कितनी कीमत आज तक चुकानी पड़ी है। उदारीकरण का दर्शन पूर्ण प्रतियोगिता के दर्शन पर आधारित है जो विकासशील देशों में दूर–दूर तक दिखायी नही देती। इन बाजारों में उत्पत्ति के साधनों की लोच पर्याप्त नही है, संस्थानात्मक तथा अन्य बाधाऐं जैसे Structural Rigidites संरचनात्मक जड़ताऐं पर्याप्त है। इन स्थितियों में आर्थिक तत्वों की जगह मानवीय तत्व ज्यादा हावी होते है। यह स्थिति अल्पाधिकार तथा एकाधिकार को जन्म देती है, साधनों के दिये हुये वितरण को प्रभावित करती है तथा उपभोक्ताओं व उत्पादक साधनों के शोषण को जन्म देती है जिससे आम व वितरण की विषमाताऐ और अधिक बढ़ती है। यह भविष्य में खतरनाक भी साबित हो सकता है। निजी क्षेत्र भी कमियों, रूग्णताओं व भ्रष्टाचार में किसी अन्य क्षेत्र से कम नही है। अन्तर मात्र इतना है कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जनता के साधनों तथा धन का शोषण, उन्ही के हित के नाम पर चोरी हुए भ्रष्टाचार के द्वारा किया जाता है जबकि निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण तथा जनता के धन का शोषण, उनको वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार के नाम पर खुलेआम किया जाता है। अनुचित मुनाफाखोरी, वस्तुओं में मिलावट, अवसर का अनुचित लाभ उठाना जब जनता को घोर आवश्यकता हो तब उनकी कालाबाजारी व जमाखोरी, भारतीय व्यापारी

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 1, Issue 02, July-Dec 2018

के जीवन का अभिन्न अंग बन गयी है। घटतौली, क्वालिटी के बारे में गलत जानकारी घटिया क्वालिटी आदि सब कुछ जनता जर्नादन को रोज सहना पड़ता है। सरकारी उपक्रम मात्र जनता के कल्याण कार्यो में डंडी मारते है तो निजी क्षेत्र कभी कभी अपने कर्मचारियों के शोषण से भी नही चूकता है। और उदारीकरण का दर्शन है कि हमें अपना भविष्य ऐसे ही निजी क्षेत्र अथवा विदेशी निजी क्षेत्र, जिसका उपनिवेशी शोषण का एक काला इतिहास है, के हाथों में सौपंना है। चूंकि यह एक ऐतिहासिक बाध्यता ही बन गयी है और अब इसे त्यागनें का सवाल नही है अतः अब मात्र कुछ सावधानियां ही बरती जा सकती है।

1. उदारीकरण का असर सही दिशा में हो रहा है या नही, इसके लिए मात्र भारत में प्रति व्यक्ति आय का तेजी से बढ़ना, गरीबो की संख्या में आयी कमी क्षेत्रीय विकास में उभरता हुआ संतुलन, तेजी से बढती बेरोजगारी राष्ट्रीय उत्पाद व आयात निर्यात का बदलती सरंचना आदि का ही अध्ययन न किया जाय, क्योंकि यह केवल अल्पकालिक हो सकता है बल्कि समूचे विश्व के आर्थिक घटनाक्रमों की Cross-sectional तथा गहन अध्ययन किया जाय। इसके लिए बहुत ही बड़ी संस्था में दक्ष अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता होगी।

2. प्रत्येक सरकारी विभाग में आडिट के अलावा, एक अर्थशास्त्री की नियुक्ति की जाये जो सरकारी काम के विवेकीकरण को सुनिश्चित कर सके। अनुचित व अनुत्पादक व्यय के लिये इन्हे ही जिम्मदार बनाया जाये।

3. मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ानें के प्रयार किये जाये ताकि वे अपने हितों की रक्षा व संवर्धन खुद कर सके व तेजी से बदलते आर्थिक वातावरण के साथ साम्य स्थापित कर सके।

4. शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि उदारीकरण के लाभों के प्रति आम जनता का euhitlement बढ़ सके व उसे वह कर सकने में सक्षम बन सकें।

References:-

1. IMF, World Economic Outlook, and May 1997: T.N Shrinivasan and Jagadish Bhagwati, "Outword Orientation and Development: Are the revisions at Right?" Yale University Economic Grawth Center Discussion Paper no. 806, 1999; and Jeffery Framket and David Romer "Does Trade Cause Growth" American Economic Review June 1999.

2. Chandrasethar, K and Geeta K.T "Economic Reforms An objective Assessment of Performance and Prospects" Southerr Economist, March 1, 1997.

3. Parilch Kirti and Radha Krishan R (ed) India Development Report 2002, Chapters 1,2&6, Oxford University Press 2002.

4. R.G. Zind 'Income Convergenee and Devergee with in and between L.D.C Groups, world Development June 1991.

5. Michael Kremer, "the O-ring Theory of Economic Development.' Suarterly Journee of Economics 108, 1993 PP 551-575.

6. Kevin M, Murphy, Andresi Shleifer and Robert W. Vishny, "Income Distribution, Market Size and Indus Irialization" Quarterly Jaurnal of Economics, 104, August 1989, PP 537-545.

7. "Globalization: Trends, Challengs and Oppartunity for Countries in Transition". By Mojeer Mrak, Seesion 1 'Globalsation and Integration of India try in the Region United Nation Industrial Development organization Vienns 2000, Chapter 3 & 4 , PP 11-32 setiend from https://www.unido.org.

8. A.P. Thirwall, Economics of Development, Nusth edition PP 217-18 Macniillan Palgrave.